R.N.I. No. UPHIN/2023/86842 वर्ष : 02 अंक : 150 | लखीमपुर–खीरी, शुक्रवार 18 अक्टूबर 2024 | पृष्ठ – 04 मूल्य – 01

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

संज्ञान दृष्टि

एक सम्पूर्ण अखबार

मोबाइल नं0–7080049049 | sangyandristinewspaper@gmail.com | website-Sangyannews.com | twitter-Sangyannews

लखीमपुर–खीरी, दिल्ली एनसीआर के साथ–साथ इंदौर, गौरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच, लखनऊ, अयोध्या, गया (बिहार)

एक नज़र

दिल्ली– इंडियन रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया, रेल मंत्रालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया, एडवांस रिजर्वेशन की समयसीमा घटाकर 60 दिन की गई, 4 महीने के बजाय 2 महीने पहले रिजर्वेशन करवा पाएंगे, इंडियन रेलवे का ये नियम 1 नवंबर 2024 से लागू होगां

लखनऊ– सपा कार्यालय में चल रही बैठक समाप्त, मुजफ्फरनगर के नेताओं के साथ हुई बैठक, सपा अध यक्ष अखिलेश यादव ले रहे थे बैठक, मीरापुर सीट पर प्रत्याशी को लेकर चर्चा, अखिलेश यादव ने टिकट दावेदारों से बात की, जल्द ही समाजवादी पार्टी प्रत्याशी का एलान करेगी, समाजवादी पार्टी अपने पास ही रखेगी मीरापुर सीट।

कानपुर– कलेक्ट्रेट में सीसामऊ उपचुनाव नामांकन की तैयारी, नामांकन की तैयारियों का डीसीपी पूर्वी ने जायजा, सेफ एंट्री, एक्जिट प्वाइंट की तैयारियां परखी, प्रत्याशियों की सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, कल से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया।

बहराइच– बहराइच हिंसा से जुड़ी सबसे बड़ी खबरहिंसा के 2 आरोपियों का हुआ एनकाउंटर, आरोपी सरफराज, तालिब का हुआ एनकाउंटर, नेपाल भागने की फिराक में थे सरफराज, तालिब।

बहराइच– बहराइच हिंसा से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, पुलिस एनकाउंटर में आरोपी सरफराज ढेर, पुलिस ने अभी मौत की पुष्टि नहीं की, दूसरे आरोपी तालिब के पैर में गोली लगी, नेपाल भागने की फिराक में थे सरफराज, तालिब।

गोरखपुर– राजकीय स्पर्श दृष्टि बाधित कॉलेज के छात्रों का हंगामा, डीएम कार्यालय पर की तोड़फोड़, खिड़की के शीशे तोड़े, 3 टीचर का ट्रांसफर रुकवाने की मांग को लेकर हंगामा, जिलाधिकारी कार्यालय पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया, समझा रही पुलिस से भी छात्रों ने की धक्का मुक्की, सेशन में 3 टीचर का ट्रांसफर हुआ,उन्हें रोका जाए–छात्र, उनके ट्रांसफर से हम लोगों की पढ़ाई रुक जाएगी–छात्र, कॉलेज में साफ–सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित हो–छात्र।

मेरठ– छेड़छाड़,मारपीट के पीड़ित परिवार पर फैसले का दबाव, फैसला नहीं करने पर डराया धमकाया जा रहा, दबंगों ने किशोरी से छेड़छाड़ कर परिवार पर हमला बोला, किशोरी के माता–पिता की पिटाई कर हाथ तोड़ा था, मुकदमा दर्ज, थाना पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं की, एसएसपी से दूसरे थाने में जांच ट्रांसफर करने की गुहार, थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र के खड़ौली गांव का मामला।

हापुड़– युवक का बीच सड़क पर हाइवोल्टेज ड्रामा, बीच सड़क पर खड़ा होकर गाड़ियों को रोका, जा रहे ट्रक के सामने बीच सड़क पर लेटा, उत्पात मचा रहे युवक को राहगीरों ने जमकर पीटा, युवक का बीच सड़क उत्पात मचाते वीडियो वायरल, नगर कोतवाली के तहसील चौराहे का मामला।

कनाडा के साथ आए अमेरिका–ब्रिटेन, भारत के पक्के दोस्त रूस ने खालिस्तान पर लगा दी ट्रूडो की क्लास

खालिस्तान। खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के पुराने विवाद ने एक बार फिर से गंभीर रूप ले लिया है। इस मामले को लेकर दोनों देशों के राजनयिक रिश्तें टूट की कगार पर पहुंचते दिख रहे हैं। इस विवाद की वदह से दोनों देश एक दूसरे के कुछ राजनयिकों को निकाल भी चुके हैं। इसी बीच मामले को लेकर रूसी मीडिया ने कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो की आलोचना की है। रूसी मीडिया चौनल आरटी ने एक मीम शेयर करते हुए ट्रूडो और उनके खालिस्तानी प्रेम को दिखाया है। मीम में म्युजिक पर डांस करते एक लड़के को जस्टिन ट्रूडो बताया गया है। वहीं लड़के के डांस को इंजॉय करते दो लोगों को खालिस्तानी अलगाववादी बताया गया है। मीम के साथ कैप्शन में लिखा गया कि भारत विरोधी रिपोर्ट ट्रूडो के घर के अंदर उसके पास मूव्स तो है लेकिन सबूत नहीं है। जब आपके हाथ से सत्ता जा रही हो और आपको वोटों की बहुत जरूरत हो तो आप बस एक ही काम कर सकते हैं– जस्ट डांस। अमेरिका ने भारत को नसीहत दी है कि वो जल्द से जल्द जांच में भारत की मदद करे क्योंकि भारत ने अभी तक जांच में सहयोग नहीं किया है। यानी अमेरिका सीधे सीधे कनाडा की तरफ जाकर खड़ा हो गया है। वैसे अमेरिका खुद भी बेबुनियाद आरोप लगा चुका है कि भारतीय एजेंट्स उसकी जमीन पर खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नून को मरवाना चाहते हैं। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से फोन पर बात की है। भारत से मुंह की खाने के बाद जस्टिन ट्रूडो ने यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर को फोन लगा डाला। ब्रिटेन ने कहा कि भारत सरकार से जुड़ी कनाडाई जांच को लेकर कनाडा के साझेदारों के संपर्क में है और उसने ओटावा की न्यायिक प्रणाली पर विश्वास जताया।

बता दें कि जस्टिन ट्रूडो की तरफ से भारत के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर वो खुद अपने घर में भी घिरे दिख रहे हैं। कनाडाई पत्रकारों ने जस्टिन ट्रूडो पर निशाना साधा है। कनाडा के वरिष्ठ पत्रकार डेनियल बोर्डमैन ने एक्स पर लिखा कि भारत के साथ रिश्ते खराब करने के बाद जस्टिन ट्रूडो एक बार फिर से मामले को लेकर जनता को पुख्ता सबूत देने में नाकाम रहे हैं। राजनयिकों को निकाला जा चुका है। हम अब भी मेरा यकीन करो दोस्त वाले फेज में हैं।

ऐसी है नायब सैनी की नई कैबिनेटः श्रुति चौधरी सबसे अमीर तो गौरव हैं सबसे युवा, 76 के श्याम सिंह सबसे उम्रदराज

हरियाणा। हरियाणा में गुरुवार को नई सरकार का गठन हो गया। नायब सिंह सैनी ने लगातार दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। नायब के साथ 13 अन्य विधायकों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इस मंत्रिमंडल में दो महिलाओं को भी मौका मिला है।

नायब कैबिनेट में श्रुति चौधरी सबसे अमीर मंत्री–नायब सिंह सैनी सरकार की नई कैबिनेट की औसत संपत्ति 30.82 करोड़ रुपये है। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी इस कैबिनेट की सबसे अमीर मंत्री हैं। तोशाम सीट पर अपने चचेरे भाई अनिरुद्ध चौधरी को हराने वाली श्रुति के पास 134 करोड़ 56 लाख 99 हजार रुपये की संपत्ति है। कैबिनेट के सबसे बुजुर्ग शामिल हैं। 48 साल की श्रुति पूर्व मंत्री श्याम सिंह राणा की संपत्ति सभी मंत्रियों में सबसे कम है। राणा ने चुनावी हलफनामे में अपनी कुल संपत्ति एक करोड़ 16 लाख 42 हजार 600 रुपये बताई है। नायब सिंह कैबिनेट की औसत संपत्ति 30 करोड़ 82 लाख 13 हजार 661 रुपये है। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 5,80,52,714 रुपये की संपत्ति बताई है।

गौरव सबसे युवा, दो मंत्री 70 पार–पलवल विधानसभा सीट से जीते गौरव गौतम नई कैबिनेट में सबसे युवा मंत्री हैं। 36 साल के गौरव ने गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नाकोत्तर किया है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के बेटी आरती सिंह राव इस कैबिनेट की दूसरी सबसे युवा मंत्री हैं। 45 साल की आरती अटेली विधानसभा सीट से जीती हैं। 50 साल से कम उम्र के तीन मंत्रियों में कैबिनेट के सबसे अमीर मंत्री श्रुति चौधरी भी मुख्यमंत्री बंसीलाल की पोती हैं। इसी तरह आरती राव भी पूर्व मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह पोती हैं। 14 सदस्यीय कैबिनेट में दो मंत्री ऐसे हैं जिनकी उम्र 70 साल से अधिक है। इनमें अनिल विज और श्याम सिंह राणा शामिल हैं। अंबाला कैंट से जीते अनिल विज की उम्र 71 साल है तो श्याम सिंह राणा 76 साल के हैं। नायब सैनी कैबिनेट की औसत उम्र 56 साल नौ महीने है।

नई कैबिनेट में तीन किसान, चार व्यवसायी–नई कैबिनेट में शामिल तीन मंत्रियों ने अपना पेशा किसानी बताया है। इन मंत्रियों में रणबीर गंगवा, राव नरबीर सिंह और श्याम सिंह राणा शामिल हैं। गंगवा ने किसानी के साथ समाजसेवा को भी अपना पेशा बताया है। कैबिनेट के सबसे युवा मंत्री गौरव गौतम ने भी अपना पेशा समाजसेवा बताया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत पांच मंत्रियों ने राजनीति को ही अपना पेशा बताया है। सैनी के अलावा अनिल विज, कृष्ण कुमार, अरविंद कुमार शर्मा और कृष्ण लाल पंवार उन मंत्रियों में शामिल हैं जिन्होंने चुनावी हलफनामे में राजनीति को अपना पेशा बताया है। इसी तरह व्यवसाय को अपना पेशा बताने वाले मंत्रियों की संख्या चार है। इन मंत्रियों में आरती सिंह राव, महिपाल ढांडा, विपुल गोयल और राजेश नागर शामिल हैं। कैबिनेट की दो महिला मंत्रियों में शामिल श्रुति चौधरी ने वकालत को अपना पेशा बताया है।

नई कैबिनेट में तीन मंत्री 12वीं पास–नायब सिंह सैनी कैबिनेट की शिक्षा की बात करें तो इसमें तीन मंत्री 12वीं पास हैं। छह के पास स्नातक, दो के पास स्नातक पेशेवर और तीन के पास स्नाकोत्तर की डिग्री हैं। राजेश नागर, रणबीर गंगवा और कृष्ण लाल पंवार कैबिनेट के सबसे कम पढ़े लिखे मंत्री हैं। तीनों मंत्री 12वीं पास हैं। इसी तरह आरती सिंह राव, महिपाल ढांडा, विपुल गोयल, राव नरबीर सिंह, अनिल विज और श्याम सिंह राणा ने स्नातक किया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी और श्रुति चौधरी के पास पेशवर स्नातक की डिग्री है। दोनों ने ही एलएलबी की है। वहीं, गौरव गौतम, कृष्ण कुमार और अरविंद कुमार शर्मा कैबिनेट के सबसे पढ़े लिखे मंत्री हैं। तीनों के पास परास्नातक की डिग्री है।

संचारी रोग नियंत्रण अभियान सीडीओ ने की समीक्षा, दिए निर्देश

अभियान का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन सुनिश्चित कराए संबंधित विभाग : सीडीओ

ईसानगर की एडीओ पंचायत का सीडीओ ने रोका वेतन, मांगा स्पष्टीकरण

प्रांजल श्रीवास्तव

लखीमपुर खीरी (संज्ञान दृष्टि)। अक्टूबर माह में संचालित संचारी रोग नियंत्रण अभियान के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की सीडीओ अभिषेक कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में विस्तृत समीक्षा की, संबंधित को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक का संचालन सीएमओ डॉ संतोष गुप्ता ने किया।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीडीओ अभिषेक कुमार ने खा कि वेक्टर जनित रोगों, संचारी रोगों तथा दिमागी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण के साथ ही इनका त्वरित एवं सही उपचार शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है। उन्होंने डीपी आरओ, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को ग्रामस्तर पर झाड़ी कटाई और नाली साफ सफाई के दिशा निर्देश दिए। निर्देश दिए की आशा डोर टू डोर सर्वे के दौरान आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरुक करते हुए स्वास्थ्य कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दें। सीडीओ ने अभियान के सभी स्टेट होल्डर विभाग माइक्रो प्लानिंग के अनुसार परिणाम मूलक कार्य के लिए निर्देशित किया।

समीक्षा के दौरान अभियान की पाटनर एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए फीडबैक के अनुसार अभियान के क्रियान्वयन में फिसड्डी ब्लॉक ईसानगर के सहायक विकास अधिकारी पंचायत का सीडीओ ने स्पष्टीकरण प्राप्त करने और वेतन रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य, नगर निकाय, पंचायती राज, बाल विकास एवं पोस्ट हर बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, पशुपालन, सूचना, दिव्यांग एवं जनशक्तिकरण और उद्यान विभाग को अभियान के तहत सौंप गए जिम्मेदारियां को निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हुए अभियान का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। सीएमओ डॉ संतोष गुप्ता ने अभियान के तहत विभिन्न विभागों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को रेखांकित किया।

प्रियंका गाँधी के खिलाफ सीपीआई ने उतारा उम्मीदवार, वायनाड उपचुनाव में एलडीएफ ने सत्यन मोकेरी पर जताया भरोसा

नई दिल्ली। सत्यन मोकेरी 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में वायनाड लोकसभा क्षेत्र से एलडीएफ उम्मीदवार होंगे। यह निर्णय सीपीआई राज्य कार्यकारिणी में लिया गया। घोषणा जल्द ही होने की संभावना है। पार्टी ने ईएस बिजिमोल और सत्यन मोकेरी सहित कुछ पर विचार किया। पिछली बार राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली एनी राजा ने पहले ही साफ कर दिया था कि वह अब मैदान में नहीं हैं। अन्नी राजा की बेटी अपराजिता का नाम भी सामने आया। चुनाव अब एक महीना भी दूर नहीं है। इसलिए मोर्चों ने तेज गति से चुनाव प्रचार शुरू करने का निर्णय लिया है. इस सीट से जीतने वाले राहुल गांधी ने रायबरेली में भी जीत हासिल की. रायबरेली से इस्तीफा देने पर उत्तर भारत में प्रतिक्रिया के डर से राहुल ने वायनाड छोड़ दिया। इसके साथ ही वायनाड में उपचुनाव के लिए मंच तैयार हो गया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने घोषणा की कि वायनाड लोकसभा उपचुनाव 13 नवंबर को होगा। वायनाड एकमात्र संसदीय क्षेत्र है जहां 47 अन्य विधानसभा क्षेत्रों के साथ उपचुनाव कराए जाएंगे। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है और उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर है। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी और नतीजे भी उसी दिन घोषित किए जाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र को बरकरार रखने के पक्ष में वायनाड लोकसभा सीट से इस्तीफा देने के बाद वायनाड में उपचुनाव हो रहे हैं। इस सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की उम्मीद है। यह प्रियंका का चुनावी डेब्यू होगा।

यूपीः राज्य कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, दिवाली से पहले होगी बढ़े डीए की घोषणा, केंद्र दे चुका है ये सौगात

उ0प्र0। यूपी के राज्य कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार दिवाली के पहले बढ़े हुए डीए की घोषण कर सकती है। दिवाली से पहले यूपी के कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि का तोहफा मिल जाएगा। इसका लाभ 17 लाख से ज्यादा राज्य कर्मियों और शिक्षकों को मिलेगा। वर्तमान में यहां के कर्मचारियों, अधिकारियों और शिक्षकों को मूल वेतन पर 50 प्रतिशत डीए मिल रहा है। केंद्र के समान ही तीन प्रतिशत वृद्धि होगी, जो जुलाई से लागू होगी।

केंद्र ने की तीन फीसदी बढ़ोतरी –केंद्र सरकार में लगभग एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते 'डीए' एवं महंगाई राहत 'डीआर' में तीन फीसदी वृद्धि की सौगात मिली है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने डीए की दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। पहली जुलाई से देय महंगाई भत्ते की दर अब 50 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत हो गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक के बाद हुई प्रेस ब्रीफिंग में यह जानकारी दी है। इससे पहले कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने 30 सितंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर डीए की दरों में बिना कोई देरी किए वृद्धि करने की मांग की थी। पत्र में कहा गया कि सामान्य तौर पर महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत में बढ़ोतरी का भुगतान, अक्तूबर के पहले सप्ताह में हो जाता था। इस बार केंद्र सरकार ने दशहरे पर भी ऐसी कोई घोषणा नहीं की।

मार्च महीने में चार फीसदी बढ़ाया गया था महंगाई भत्ता–मार्च में सरकार ने महंगाई भत्ते में 4: की बढ़ोतरी की थी, जो जनवरी 2024 से प्रभावी होगा, जिससे कुल महंगाई भत्ता मूल वेतन के 46: से बढ़कर 50: हो गई थी। इस भत्ते की गणना पिछले 12 महीनों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित है, यह सरकारी वेतन और पेंशन के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, जब महंगाई भत्ता मूल वेतन का 50: हो जाता है, तो मकान किराया भत्ता समेत कई भत्ते स्वतः संशोधन के दायरे में आ जाते हैं।

कर्मचारियों को तीन महीने का एरियर भी मिलेगा–केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने का एलान जुलाई से दिसंबर महीने तक के लिए किया गया है। ऐसे में कर्मचारियों को अक्तूबर महीने के वेतन के साथ जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने के एरियर का भी भुगतान किया जाएगा।

ऐसी ही व्यवस्था प्रदेश के कर्मचारियों के लिए भी लागू होगी। यूपी के कर्मचारियों को भी जुलाई से सितंबर का एरियर मिलेगा। अक्तूबर की सेलेरी में बढ़ा हुआ डीए आ जाएगा।

खाद वितरण में अनियमितता पाए जाने पर सीडीओ के निर्देश पर सोसाइटी के सचिव निलंबित

धर्मेश शुक्ला

लखीमपुर खीरी (संज्ञान दृष्टि)। तहसील गोला के अंतर्गत बी–पैक्स मैलानी सोसाइटी में उर्वरक वितरण में अनियमितता करने का प्रसारित वीडियो का संज्ञान लेकर सीडीओ अभिषेक कुमार ने एडीओ कृषि, एडीओ सहकारिता और एडीसीओ की त्रिस्तरीय समिति गठित करते हुए जांच कराई।

गठित त्रिस्तरीय समिति ने खाद की गुणवत्ता व भंडारण का निरीक्षण किया। जांच के दौरान उर्वरक वितरण में बिना ई–पास मशीन के वितरण पाया गया। मौके पर संबंधित समिति के सचिव अनुपस्थित भी मिले। पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट समिति द्वारा प्राप्त होने पर सीडीओ के निर्देश पर सहायक आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता रजनीश प्रताप सिंह ने सोसायटी के सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। सीडीओ से प्राप्त निर्देशों के क्रम में विधिक कार्यवाही भी शुरू कर दी है।

सीडीओ अभिषेक कुमार ने निर्देश दिए कि सभी सोसाइटी पर सचिव नियमानुसार एवं रोस्टर के अनुसार उपस्थित रहे। सहकारिता के अधिकारी गण भ्रमणशील रहकर समितियो का निरीक्षण करें। ई पास मशीन के टॉप–20 क्रेताओ (खरीददारो) की लिस्ट निकाल कर उसका वेरिफिकेशन भी कराया जाए। किसानों को ई पास के जरिए नियमानुसार खाद वितरित किया जाए।

सम्पादकीय

क्रियान्वयन के 19 वर्षों के बाद आरटीआई अधिनियम के रिकॉर्ड पर एक नजर

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम ने 12 अक्टूबर, 2024 को 19 वर्ष पूरे कर लिये। जब इसे पहली बार लागू किया गया था, तो इसने नागरिकों में बहुत उत्साह पैदा किया था, जिन्होंने अपनी सरकार से जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की संभावना देखी थी। हम भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं, लेकिन इसका आम नागरिकों के लिए कल्याण और सुशासन में परिवर्तन अभी तक नहीं हुआ है। लोकतंत्र को श्लोगों द्वारा लोगों के लिए लोगों का शासनश के रूप में परिभाषित किया जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब कोई आम नागरिक किसी सरकारी कार्यालय में जाता है, तो वह अक्सर आहत, अपमानित और निराश महसूस करता है। पहली बार, हमारे पास ऐसा कानून था जो व्यक्तिगत नागरिक की संप्रभुता को मान्यता देता था और नागरिक की सरकार और सभी लोक सेवकों पर सर्वोच्चता को भी स्वीकार करता था। इसने इस तथ्य को भी मान्यता दी कि सरकार के पास नागरिकों की ओर से सभी जानकारी होती है। सशक्त नागरिक अपनी शिकायतों के निवारण और भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए आरटीआई का इस्तेमाल करते थे।

आरटीआई अधिनियम में ऐसी सूचनाओं की सूची नहीं है, जिन्हें नागरिक प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि इसमें ऐसी सूचनाओं की एक छोटी नकारात्मक सूची है, जिन्हें नागरिक को देने से मना किया जा सकता है। बाकी सभी सूचनाओं को नागरिकों के साथ साझा किया जाना था। यह दुनिया के सबसे बेहतरीन पारदर्शिता कानूनों में से एक था, लेकिन यह वायदा किये गये परिणाम और बेहतर शासन नहीं दे रहा है, क्योंकि विभिन्न उपाय और उन्हें लागू करने वाले अनेक अधिकारी कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसे विकृत कर रहे हैं। यह अधिनियम मानता है कि सभी मौजूदा सूचनाएं किसी नागरिक को मांगे जाने पर दी जानी चाहिए और अगर कोई लोक सेवक बिना उचित कारण के 30 दिनों के भीतर सूचना देने से मना करता है, तो उस पर व्यक्तिगत जुर्माना लगाया जा सकता है। असंतुष्ट नागरिकों के लिए, यह विभाग के भीतर एक वरिष्ठ अधिकारी के पास अपील करने का प्रावधान करता है और यदि यह संतोषजनक नहीं है, तो कानून सूचना आयोग के रूप में एक दूसरा अपीलीय प्राधिकरण बनाता है। इसने आयोगों को अपने आदेशों को लागू करवाने के लिए पर्याप्त अधिकार दिये। सूचना आयुक्तों का चयन प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और केंद्रीय आयोग के लिए एक अन्य मंत्री और राज्य आयोगों के लिए मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता और एक अन्य मंत्री वाली समिति द्वारा किया जाना था। यह आरटीआई अधिनियम की कमजोर कड़ी बन गयी। आयुक्तों का चयन बिना किसी पारदर्शी प्रक्रिया के किया गया और, ज्यादातर मामलों में, पद ऐसे लोगों को दिये गये जो नौकरशाही और राजनीतिक नेटवर्क में काम कर सकते थे। नतीजतन, बड़ी संख्या में ऐसे आयुक्तों का चयन किया गया, जिन्हें न तो पारदर्शिता के प्रति कोई झुकाव था और न ही इसके प्रति कोई प्रेम। उनमें से कई ने इन पदों को सेवानिवृत्ति के बाद की नौकरी या सेवा में रहते हुए किए गये उपकारों के पुरस्कार के रूप में देखा। वे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) से उत्पन्न होने वाले मौलिक अधिकार के रूप में सूचना के अधिकार के महत्व को नहीं पहचानते या समझते थे। कानून में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि सूचना मांगने के लिए कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। आयुक्तों और न्यायालयों ने आवेदकों से यह पूछना शुरू कर दिया कि वे सूचना क्यों चाहते हैं। यदि उत्तर उन्हें संतुष्ट नहीं करता, तो वे आवेदकों को सूचना देने से इनकार कर देते हैं। यह इस तथ्य से और भी बढ़ गया है कि देश में कई आयुक्त किसी भी गंभीरता से काम नहीं करते हैं। उनमें से कई सप्ताह में 40 घंटे भी काम नहीं करते हैं। अधिकांश मामलों में मामलों का निपटारा बिल्कुल अस्वीकार्य है। कई आयुक्त एक महीने में 50 से 100 मामलों का निपटारा करते हैं। उन्हें प्रति माह लगभग 400 से 500 मामलों का निपटारा करना चाहिए, जैसा कि कुछ करते हैं। एक बेंचमार्क के रूप में, मैं उल्लेख कर सकता हूं कि भारतीय उच्च न्यायालयों में मामलों का औसत निपटान, जो अधिक जटिल हैं, प्रति माह 200 मामलों से अधिक है। सूचना आयोगों में लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है और आयोगों में आरटीआई मामलों में छह महीने से चार साल तक की देरी हो रही है। नागरिकों की कानून को लागू करने में रुचि कम हो रही है और लोक सेवक कानून में उल्लिखित अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने लगे हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि नागरिकों का कानून में विश्वास खत्म हो रहा है। आरटीआई को एक और बड़ा झटका आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(जे) की घोर गलत व्याख्या है। इस धारा का उद्देश्य ऐसी सूचना को छूट देना था जो किसी व्यक्ति की निजता पर आक्रमण करती हो। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि निजता को परिभाषित करना कठिन हो सकता है, भारतीय संसद ने इस धारा को सावधानीपूर्वक और कुशलता से तैयार किया था।

यह धारा श्ऐसी सूचना को छूट देती है जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसके प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है, या जो व्यक्ति की निजता पर अनुचित आक्रमण करेगी जब तक कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, संतुष्ट न हो कि व्यापक सार्वजनिक हित ऐसी सूचना के प्रकटीकरण को उचित ठहराता है। बशर्ते कि वह सूचना, जिसे संसद या राज्य विधानमंडल को देने से इनकार नहीं किया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति को देने से इनकार नहीं किया जायेगा। आम तौर पर,सार्वजनिक अभिलेखों में अधिकांश जानकारी सार्वजनिक गतिविधि से उत्पन्न होती है। जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) को यह तय करना होता है कि क्या यह निजता का उल्लंघन है। निजता का संबंध घर के भीतर के मामलों, व्यक्ति के शरीर, यौन वरीयताओं आदि से है। यह संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अनुरूप है। फिर पीआईओ को अपना व्यक्तिपरक निष्कर्ष दर्ज करना चाहिए कि वह संसद या राज्य विधानसभा को मांगी गयी जानकारी नहीं देगा। दुर्भाग्य से कई लोक सेवक, आयुक्त और अदालतें केवल यह कहकर सूचना देने से इनकार कर देती हैं कि यह व्यक्तिगत जानकारी है। यह कानून या संविधान के अनुरूप नहीं है। यह अनुच्छेद 19 (1)(ए) के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों के लिए एक बड़ा नुकसान हो सकता है। नागरिकों और मीडिया को सूचना के अपने अधिकार की रक्षा करनी चाहिए, ऐसा न करने पर आरटीआई अधिनियम सूचना देने से इनकार करने के अधिकार में बदल जायेगा।

सत्ता का इकबाल कायम करें मोदी

नरेन्द्र मोदी सरकार के लिए इस समय आंतरिक और विदेश मामलों में कठिन परीक्षा की घड़ी चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी से अपेक्षा है कि चुनाव में जीत–हार की फिक्र से ऊपर उठकर इस समय वे गंभीरता से हालात का मुआयना करें, विशेषज्ञों की राय लेकर फैसले करें और देश को आश्वस्त करें कि हर हाल में जनता के हितों की रक्षा होगी। मुंबई में दशहरे के दिन भीड़ भरे इलाके में अजित पवार गुट एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। इस हत्या की जिम्मेदारी गुजरात की जेल में बंद गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई ने ली। कायदे से गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों, गृहमंत्रियों के साथ–साथ केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह को इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी कि उनकी निगरानी में जेल से एक बड़े अपराध को अंजाम दिया गया। लेकिन फिलहाल इस मामले में आरोपियों की कितनी जल्दी धर–पकड़ हो गई है इसी बात का श्रेय लूटा जा रहा है। मुमकिन है 20 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले इस मामले में कुछ लोगों को अपराधी साबित करने के सरकार की सख्ती का दावा भी ठोंका जाए। लेकिन क्या लारेंस बिश्नोई का सच सामने आ पाएगा, ये सवाल कानूनी उलझनों में फंसा हुआ है। बता दें कि लारेंस बिश्नोई को गुजरात की साबरमती जेल में रखा गया है, जो हाईप्रोफाइल मुजरिमों के लिए बनी है। इसमें किसी आरोपी से पूछताछ के लिए सख्त नियम बने हैं। लारेंस बिश्नोई पर सीआरपीसी की धारा 268 के तहत, अगस्त 2023 तक के लिए जेल से बाहर निकलने पर रोक लगी हुई थी। अब नये आदेश के मुताबिक, बीएनएसएस की धारा 303 के तहत यह पाबंदी अगस्त 2025 तक बढ़ा दी गई है। अगर कोई भी पुलिस टीम, अधिकारी या एजेंसी लॉरेंस बिश्नोई से किसी मामले में पूछताछ करना चाहती है, तो उन्हें एक न्यायिक आदेश लेकर आना होगा। साथ ही उसके खिलाफ चल रही किसी भी जांच को जेल परिसर के भीतर ही अंजाम दिया जाएगा। वैसे साबरमती जेल प्रशासन का कहना है कि लारेंस बिश्नोई जेल के भीतर से कोई गिरोह नहीं चला रहा है, उसके पास कोई मोबाइल फोन या ऐसा जरिया नहीं है, जिससे वो बाहरी दुनिया से संपर्क रख सके। मगर सिद्दीकी हत्याकांड की शुरुआती जांच में अगर लारेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया तो इसे क्या केवल साबरमती जेल प्रशासन के बयान के आधार पर नजरंदाज किया जा सकता है, यह विचारणीय है। यह तय है कि लारेंस बिश्नोई को अब पूछताछ के लिए गुजरात से बाहर नहीं लाया जाए, इसका कानूनी इंतजाम कर लिया गया है। लेकिन इसी साबरमती जेल में यूपी का माफिया डॉन अतीक अहमद भी 2019 से बंद था और पिछले साल मार्च में उसे गुजरात से यूपी शिफ्ट किया गया, इसके बाद अप्रैल में किस तरह उसे और उसके भाई को पुलिस सुरक्षा के बीच ही मार दिया गया, यह दृश्य पूरे देश ने देखा है। इस तरह की घटनाओं पर कुछ तालियां बज सकती हैं कि एक माफिया को मिट्टी में मिलाने की हिम्मत सरकार ने दिखाई, लेकिन वहीं सवाल भी उठते हैं कि जब अतीक अहमद को बाहर लाया जा सकता है तो लारेंस बिश्नोई से गुजरात के बाहर पूछताछ क्यों नहीं की जा सकती। बाबा सिद्दीकी की हत्या की घटना को केवल पैसों के लिए किए गए अपराध की तरह नहीं देखा जा सकता, क्योंकि लारेंस बिश्नोई सीधे–सीधे लोकतांत्रिक सरकार की सत्ता को चुनौती दे रहा है, ठीक वैसे ही जैसे एक वक्त में दाऊद इब्राहिम का रवैया था। दाऊद इब्राहिम तो भारत के प्रमुख वांछित अपराधियों में शामिल है, वह आतंकवादी है। लेकिन लारेंस बिश्नोई को आतंकवादी कहने की जगह भारत के कई सोशल मीडिया हैंडल्स पर उसका महिमामंडन हो रहा है। उसे बॉलीवुड के लोगों, खालिस्तानियों, हिंदुत्व का विरोध करने वालों के लिए काल की तरह बताया जा रहा है। उसकी तस्वीर इस अंदाज में पोस्ट की जा रही हैं, मानो उसने बड़ी जांबाजी का काम किया है। एक अपराधी को नायक बनाने की यह भूल समाज को विनाश की तरफ ले जाने वाली है, क्योंकि इस तरह युवाओं को भटकाना और आसान हो जाता है। वैसे ही इस समय हमारे युवाओं का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। रोजगार और अच्छी शिक्षा की तलाश में हर बरस लाखों युवा विदेश जा रहे हैं और इनमें बड़ी संख्या कनाडा जाने वालों की है। लेकिन इस वक्त कनाडा और भारत के संबंध सबसे नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। 14 अक्टूबर को दोनों देशों ने एक–दूसरे के छह–छह राजनयिकों को निष्कासित किया है। दरअसल पिछले वर्ष कनाडाई नागरिक और सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा ने इसमें भारत की भूमिका पर सार्वजनिक तौर पर सवाल उठाए थे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने वहां की संसद में इस बारे में बयान दिया था। तब भारत ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था और साथ ही कनाडा को भारत–विरोधी शक्तियों को शरण न देने की सलाह दी थी। लेकिन भारत की सलाह का कोई असर कनाडा पर नहीं हुआ और अभी जस्टिन ट्रूडो ने फिर कह दिया कि भारत सरकार के अधिकारी पिछले जून में सरे में सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल थे। इसके बाद कनाडाई प्रशासन ने एक प्रेस कांफ्रेंस में यह कहा कि भारत की जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का गिरोह या उसके एजेंट कनाडा में इस हत्या के पीछे हैं। इस तरह कनाडा ने सीधे–सीधे भारत सरकार पर एक गैंगस्टर के साथ मिलकर काम करने का गंभीर आरोप लगाया। यह वैश्विक स्तर पर भारत का अपमान है। वहीं अमेरिका में भी अब भारत के खिलाफ इसी तरह की बातें हो रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने अगस्त में कनाडा के दौरे पर कहा था कि अमेरिका कनाडा के साथ हर स्तर पर सहयोग कर रहा है ताकि निज्जर हत्याकांड मामले की तह तक पहुंचा जा सके। उन्होंने निज्जर की हत्या को एक त्रासदी बताया था। वहीं इस मंगलवार को अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि जब कनाडाई मामले की बात आती है, तो हमने स्पष्ट कर दिया है कि आरोप बेहद गंभीर हैं और उन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत है। हम चाहते थे कि भारत सरकार कनाडा को उसकी जांच में सहयोग दे। उन्होंने (भारत) वह रास्ता नहीं चुना है। अमेरिका का यह रवैया बता रहा है कि फिलहाल वह भारत की अपेक्षा कनाडा की दोस्ती को तवज्जो दे रहा है। इन हालात में अब नरेन्द्र मोदी को सोचना है कि वे अमेरिकी धरती पर मोदी–मोदी के नारे सुनकर गदगद होते रहें, ओबामा से लेकर ट्रंप और बाइडेन तक सबको अपना करीबी मित्र बताते रहें या फिर भारत के हितों के बारे में सोचकर कोई कड़ी टिप्पणी इन मामलों पर करें। बेशक भारत का विदेश मंत्रालय अपनी तरफ से सख्ती दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा है। उसके प्रवक्ता भारत पर लग रहे आरोपों पर कड़ा जवाब दे रहे हैं। लेकिन ये वक्त पं. नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी की तरह पश्चिमी ताकतों, खासकर अमेरिका को जवाब देने का है। अगर कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों से प्रेरणा लेने में श्री मोदी को असुविधा हो तो पोरस की मिसाल भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। 340 ईसा पूर्व से 315 ईसा पूर्व तक झेलम से लेकर चिनाब तक फैले पंजाब–सिंध प्रांत में पोरस का साम्राज्य फैला था और विश्वविजय पर निकले सिकंदर के अभियान को पोरस की कड़ी चुनौती मिली थी। ऐतिहासिक कथा के मुताबिक दोनों के बीच हुए युद्ध के बाद जब पोरस को बंदी बनाकर सिकंदर के सामने पेश किया गया, तब पोरस ने सिकंदर से कहा था कि उनके साथ वही सलूक करना चाहिए जो एक राजा, दूसरे राजा के साथ करता है। इस कथा में तथ्य कितना है, यह अलग पड़ताल का विषय है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संबंधों और राजनयिक शिष्टाचार में सम्मान और बराबरी का सबक इससे जरूर लिया जा सकता है।

कनाडा और अमेरिका से संबंधों में आ रही इस तल्खी और भारत के अपमान के बाद भारत सरकार के अधिकारियों को नहीं, खुद प्रधानमंत्री मोदी को आगे बढ़कर कनाडा और अमेरिका दोनों को सीधे जवाब देकर अपनी मजबूत स्थिति दिखाना चाहिए और बताना चाहिए कि भारत सरकार किसी गैंगस्टर के साथ मिलकर काम नहीं करती है।

घाटी में महका लोकतंत्र

आखिरकार तमाम ऊहापोह, सुरक्षा चुनौतियों तथा विदेशी दखल की तमाम आशंकाओं को निर्मूल करते हुए जम्मू–कश्मीर के जनमानस ने स्पष्ट सरकार बनाने का जनादेश दिया है। जनता ने विकास और शांति की आकांक्षा के साथ दिल खोलकर मतदान किया और अपनी उम्मीदों की सरकार चुनी है। घाटी में दशकों तक अब्दुल्ला परिवार के शासन के अनुभव के मद्देनजर घाटी के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भरोसा जताया। बुधवार को उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनकी सार्थक पहल यह रही कि उन्होंने जम्मू–कश्मीर की राजनीति के दो ध्रुव बने कश्मीर घाटी व जम्मू क्षेत्र के जनमानस को साथ लेकर चलने का संकल्प दोहराया है। इस कड़ी में उमर अब्दुल्ला ने सुरिंदर चौधरी को राज्य का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उमर ने कहा भी कि 'चौधरी को मैंने इसलिए उप मुख्यमंत्री बनाया, ताकि जम्मू के लोगों को महसूस हो सके कि उनकी भी राज्य की सत्ता में घाटी जितनी भागीदारी है। आगे भी ऐसे ही प्रयास होते रहेंगे।' निस्संदेह, यह सकारात्मक राजनीति का उज्ज्वल पक्ष है, सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का। उल्लेखनीय है कि सुरिंदर चौधरी जम्मू से चुनकर आए हैं। नौशेरा से विधायक बने सुरिंदर चौधरी ने विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रांत अध्यक्ष रवींद्र रैना को हराया था। बहरहाल, भले ही अब अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद जम्मू–कश्मीर विधानसभा का स्वरूप पहले जैसा नहीं रह गया, लेकिन इसके बावजूद जम्मू–कश्मीर के लोगों ने स्पष्ट जनादेश देकर एक स्थिर सरकार की बुनियाद जरूर रखी है। केंद्र शासित प्रदेश में एक दशक बाद हुए विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का खासा उत्साह नजर आया। कहीं न कहीं जनता ने स्पष्ट संदेश भी दिया कि वे आतंकवाद व अलगाववाद से छुटकारा चाहते हैं। जाहिरा तौर पर नई सरकार के सामने व्यापक जनाकांक्षाओं को पूर्ण करने की चुनौती होगी। यह दायित्व सरकार को इस बात को ध्यान में रखकर निभाना होगा कि केंद्रशासित प्रदेश में उपराज्यपाल के पास व्यापक अधिकार हैं। बहरहाल, ऐसे में नवनिर्वाचित सरकार और केंद्र का दायित्व है कि घाटी के लोगों ने जिस मजबूत लोकतंत्र की आकांक्षा जतायी है, उसे पूरा करने में भरपूर सहयोग करें। एक समय राज्य में मतदाता डर के मारे मतदान करने हेतु नहीं निकलते थे। मतदान का प्रतिशत बेहद कम रहता था। इस बार मतदाता निर्भीकता के साथ मतदान करने निकले। जनता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के संकल्प को सकारात्मक प्रतिसाद दिया है। यद्यपि लोकसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाबी नहीं मिल पायी थी, लेकिन जनता ने उन्हें राज्य में सरकार चलाने का स्पष्ट जनादेश दिया है। वहीं दूसरी ओर, इस भारी मतदान व स्पष्ट बहुमत का एक निष्कर्ष यह भी है कि लोग घाटी में शांति और सुकून चाहते हैं। जम्मू–कश्मीर सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर प्रयास करना होगा कि इस क्षेत्र में शांति कायम होने के साथ विकास की नई बयार चले। जिसमें आम नागरिक खुद को सुरक्षित अनुभव करते हुए राष्ट्रीय विकास की धारा के साथ–साथ कदमताल कर सके। बहरहाल, जम्मू–कश्मीर में नई सरकार को व्यापक जनाकांक्षाओं को पूर्ण करते हुए बदली हुई शासन व्यवस्था के साथ भी साम्य स्थापित करना है। इस बात का अहसास उमर अब्दुल्ला को भी है कि शासन चलाने में अब पहले जैसी स्वतंत्रता नहीं होगी क्योंकि राज्यपाल के पास व्यापक शक्तियां हैं। विश्वास किया जाना चाहिए कि कम से कम सीमावर्ती घाटी की संवेदनशीलता को देखते हुए इस केंद्रशासित प्रदेश में वैसा टकराव देखने को नहीं मिलेगा, जैसा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और उम्मीद की जानी चाहिए कि नये मुख्यमंत्री को कानून व्यवस्था से लेकर अन्य प्रशासनिक मामलों में एलजी के आगे लाचार नहीं होना पड़ेगा। विश्वास करें कि नई सरकार को प्रशासनिक मामलों में नौकरशाही का पर्याप्त सहयोग मिलता रहेगा। नीति–नियंताओं को ध्यान रखना होगा कि सरकार चलाने में किसी भी तरह का अनावश्यक व्यवधान कालांतर अशांति का वाहक बनेगा। उम्मीद करें कि यथाशीघ्र पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद जम्मू–कश्मीर में प्रशासन की विसंगतियां दूर की जा सकेंगी।

आज का राशिफल

मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन

मेष :– समय के साथ समझौता करके चलने का प्रयास करें। कार्यक्षेत्र को ही अपनी पूजा समझें और स्वयं को उसी ओर केंद्रित करें। पत्नी के साथ मधुर वणी का प्रयोग करें। रोजगार में लाभकारी स्थिति रहेगी।

वृषभ :– हर घटना से आपको सीख लेने की जरूरत है। नये क्षेत्र में निवेश से पूर्व जानकार लोगों से विचार–विमर्श करें। भविष्य के प्रति निराशाजनक विचारों को मन पर हावी न होने दें। नये व्यावसायिक यात्राओं का योग है।

मिथुन :– निकट संबंधों में मधुर संवाद से अपनी सुंदर छबि बनायें। कुछ महत्वपूर्ण अभिलाषाओं की पूर्ति होने के आसार हैं। सामान्य दिनचर्या के साथ बीत रहे जीवन में उत्साह का अभाव रहेगा। घर में खुशहाली होगी।

कर्क :– भविष्य संबंधी कुछ चिंताएं उत्पन्न होंगी। किसी कार्य को छोटा–बड़ा समझने के बजाए अपने कर्त्तव्यों का सही ढ़ंग से निर्वहन करें। वर्तमान कार्य से मन असंतुष्ट रहेगा। जरूरी कायरे में आलस्य का त्याग करें।

सिंह :– पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति हेतु चिंता उत्पन्न होगी। अपने स्वास्थ के प्रति लापरवाही न बरतें एवं जीवन साथी के स्वास्थ के प्रति भी ध्यान दें। किसी बड़े आयोजन हेतु समुचित साधन लिए मन प्रयत्नशील होगा।

कन्या :– परिवार की छोटी–छोटी बातों बाहरी लोगों से न कहें। भावना से उद्वेलित मन संबंधियों के सुख–दुख के प्रति चिंतित होगा। किसी नयी दिशा में सकारात्मक सोच अवश्य रंग लायेगी। रोजगार में व्यस्तता रहेगी।

तुला :– महत्वाकांक्षी अभिलाषाएं मन में असन्तुष्ट पैदा करेंगी। तामसिक विचारों को मन से दूर ही रखें। विपरीतलिंगी संबंधों के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति में व्यय अपेक्षित है।

वृश्चिक :– स्वयं को सही दिशा और लक्ष्य की ओर केंद्रित करें तभी जीवन में सही प्रगति कर सकते हैं। किसी पुराने संबंध के प्रति विशेष निकटता की अनुभूति करेंगे। ग्रहों की अनुकूलता से अवरोधित कार्य हल होंगे।

धनु :– किसी भी प्रयास में आर्थिक अभाव अवरोधक होगा। साहस व बुद्मित्ता से पुरानी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर सुख की अनुभूति करेंगे। विषम स्थितियों के मध्य परिश्रम व लगन से प्रगति की ओर अग्रसर होंगे।

मकर :– बुद्धिमत्ता व परिश्रम का मिले–जुले संयोग का भरपूर लाभ उठाएंगे। आर्थिक क्षेत्र में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। सफलताएं आंतरिक क्षमताओं का एहसास कराएंगी। संतान संबंधी दायित्वों की पूर्ति होगी।

कुंभ :– शासन–सत्ता में व्यस्तता बढ़ेगी। मन आर्थिक सुदृढ़ता हेतु चिंतित होगा। सामाजिक सक्रियता से मान–प्रतिष्ठा बढ़ेगी। राजनीति को ग्रहों की अनुकूलता का लाभ मिलेगा। परिजनों के सुख–दुख के प्रति मन चिंतित होगा।

मीन :– कोई छोटी बात भी परिवार में तनाव का कारण बन सकती है। महत्वपूर्ण प्रयत्न की सार्थकता हेतु नये उत्साह का संचार होगा। सामाजिक गतिविधियों में क्रियाशीलता बढ़ेगी। भावनात्मक अभिव्यक्ति से संबंध मधुरत होंगे।

खाना खजाना / सेहत / ब्यूटी

इस तरह खरीदें डेकोरेशन आइटम्स, राजमहल जैसे

जगमगा उठेगा आपके सपनों का आशियाना

त्योहार आदि के मौके पर लोग घरों को सजाने के लिए तमाम तरह के डेकोरेशन आइटम्स की खरीददारी करते हैं। घरों को सजाना आसान होने के साथ काफी मुश्किल होता है। अक्सर लोग अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए आर्टिफिशियल फूलों के साथ, स्टैचू और वॉल पेंटिंग खरीदकर लाते हैं। लेकिन समस्या यह होती है कि इन आइटम्स को कहां और किस जगह पर लगाया जाए। वहीं क्या ये डेकोरेशन आइटम्स घर को सुंदर दिखाएं। ऐसी तमाम तरह की बातें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं।

हालांकि इस बात में कोई शक नहीं है कि घर की साज–सज्जा के लिए यदि सही चीज का चुनाव किया जाए, तो एक ही डेकोरेटिव आइटम पूरे घर को चमका सकते हैं। घर का सामान खरीदते समय यदि आप कुछ बातों का ध्यान रखती हैं, तो आप घर को बेहतर तरीके से सजा सकती हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको होम डेकोर के कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे आप डेकोरेशन आइटम खरीदने के दौरान अपना सकती हैं।

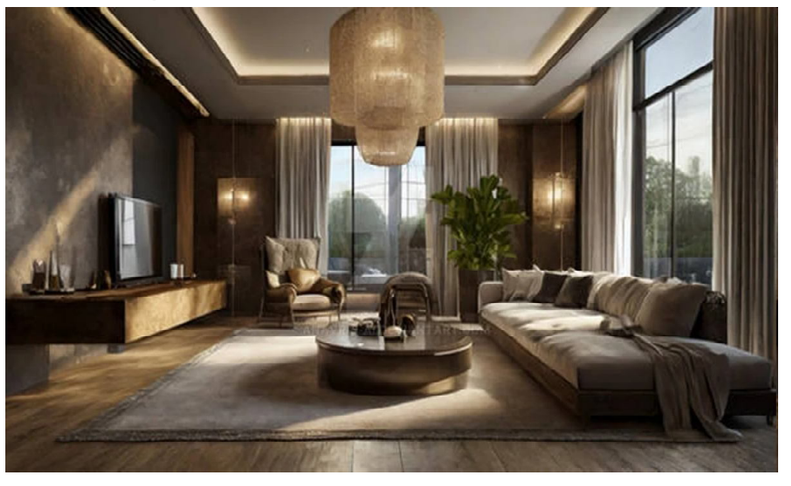

टिकाऊ और मजबूत डेकोरेशन आइटम–मार्केट में अलग–अलग तरह के डेकोरेशन आइटम्स मिलते हैं। कुछ आइटम्स इतने कमजोर होते हैं, जिन पर हल्का सा धक्का लग जाए तो वह टूट जाएंगे। वहीं कुछ सामान ऐसे होते हैं, जो मजबूत होते हैं। ऐसे में अगर आप किसी आइटम को खरीदने के लिए अच्छा खासा बजट खर्च कर रहे हैं, तो आप मजबूत और टिकाऊ सामान लें।

फर्नीचर–घर को भरा और सुंदर दिखाने के लिए अक्सर लोग डिजाइनर फर्नीचर और सोफा खरीदना पसंद करते हैं। कई बार हम काम के लिए अलग–अलग फर्नीचर खरीदते हैं। ऐसे में आप अलग–अलग फर्नीचर खरीदने की जगह मल्टीपर्पज फर्नीचर ले सकते हैं। बेड और सोफा अलग–अलग लेने की बजाय आप सोफा कम बेड ले सकते हैं। मार्केट में इस तरह के तमाम फर्नीचर मौजूद हैं, जो बजट और समय दोनों की बचत करते हैं।

इको फ्रेंडली आइटम्स–डेकोरेशन का सामान खरीदने के दौरान प्रयास करें कि आप ऐसा सामान खरीदें, जो इको फ्रेंडली हों। ऐसी चीजों जिनको खराब होने पर उन्हें फेंकने से किसी तरह का कोई नुकसान न हो। आप घर के लिए आर्टिफिशियल प्लांट की जगह रियल इंडोर और आउटडोर प्लांट खरीदें।

मल्टी लेयर होगा पीएम का सुरक्षा का घेरा, 5000 सुरक्षाकर्मी होंगे तैनातय ड्रोन से निगरानी

नई दिल्ली। पीएम मोदी के दौरे को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। पीएम का सुरक्षा मल्टी लेयर होगा। इस दौरान 5000 सुरक्षाकर्मी तैनात होंगे। साथ ही रूफ टॉप फोर्स तैनात होगी और ड्रोन सर्विलांस से निगरानी की जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा घेरा मल्टी लेयर होगा। सुरक्षा में एसपीजी, एटीएस समेत 5000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक चप्पे–चप्पे पर सशस्त्र जवानों की निगहबानी रहेगी। वीआईपी रूट पर रूफ टॉप फोर्स, ड्रोन सर्विलांस से निगरानी की जाएगी। सिगरा स्टेडियम और हरहुआ के हरिहरपुर में शंकरा नेत्रालय के प्रस्तावित मार्गों का बुधवार को पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने निरीक्षण किया। वीवीआईपी मंच, सभा स्थल, कार्यक्रम स्थल के प्रवेश और निकास द्वार, बैरिकेडिंग, अस्थायी पार्किंग स्थल, सुरक्षा बलों की तैनाती आदि का निरीक्षण किया। वहीं, वीआईपी कार्यक्रम के दौरान शहरवासियों की सुविधाओं को देखते हुए यातायात डायवर्जन प्लान पहले से लागू कराने आदि को लेकर डीसीपी यातायात को निर्देशित किया।

पुलिस आयुक्त ने कहा कि वीवीआईपी के सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन हो। निरीक्षण में अपर पुलिस आयुक्त कानून व व्यवस्था एस. चन्नप्पा, पुलिस उपायुक्त यातायात व प्रोटोकॉल ह्रदेश कुमार, पुलिस उपायुक्त काशी जोन गौरव बंशवाल, पुलिस उपायुक्त वरूणा जोन चन्द्रकांत मीना, अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा सरवणन टी., अपर पुलिस उपायुक्त यातायात राजेश पांडेय आदि मौजूद रहे।

एसपीजी पहुंची, आज से एएसएल बैठक और निरीक्षण– प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे को देखते हुए सुरक्षा–व्यवस्था का खाका खींचने के लिए एसपीजी की टीम बुधवार की शाम पहुंच गई। बृहस्पतिवार को बाबतपुर एयरपोर्ट पर एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग (एएसएल) की बैठक समेत प्रस्तावित कार्यक्रम स्थलों का एसपीजी की टीम निरीक्षण करेगी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था की कमान एसपीजी संभालेगी। बाबतपुर एयरपोर्ट पर सभी विभागों के साथ एसपीजी एएसएल बैठक करेगी और फिर एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थलों तक का रूट रिहर्सल समेत अन्य कई बिंदुओं पर सुरक्षा व्यवस्था को परखेगी। प्रधानमंत्री के स्वागत और कार्यक्रम में शामिल होने वाले जनप्रतिनिधियों, भाजपा पदाधिकारियों, अधिकारियों समेत अन्य के नामों की सूची पर शुक्रवार को अंतिम मुहर लगेगी। शनिवार को पीएम की डमी फ्लीट रिहर्सल, टच एंड गो और कार्यक्रम स्थलों को एसपीजी अपने कब्जे में ले लेगी।

शिक्षकों की तरह ही अनिवार्य हो स्कूल के क्लर्क, लाइब्रेरियन और परिचारियों के लिये ऑनलाईन हाजरी :शिक्षक संघ सूत्र

रंजीत कुमार

बिहार (संज्ञान दृष्टि)। बिहार मे इन दिनों शिक्षा विभाग शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर काफी चर्चा मे है। शिक्षा विभाग इसे दुरुस्त करने को लेकर कई प्रकार के रोज नये–नये फरमान जारी कर रही है। जिससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार का दावा बिहार सरकार कर रही है। खासकर शिक्षकों की स्कूलों मे उपस्थिति को लेकर कई शिकायतें आ रही थी। जिसे पटरी पर लाने के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और एक ई शिक्षा कोष एप के माध्यम से शिक्षकों की हाजरी अनिवार्य कर दी। अब शिक्षक स्कूलों में अपनी उपस्थिति ई शिक्षा कोष एप के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज कर रहे हैं।

लेकिन स्कूलों में सबसे बड़ी समस्या अब यह आ रही है की इस एप से हाजरी केवल शिक्षक ही बना रहे हैं। जबकि स्कूल के अन्य स्टॉफ जैसे – लिपिक या क्लर्क, लाइब्रेरियन, परिचारी अपनी उपस्थिती रजिस्टर पर ही ऑफलाइन दर्ज कर रहे हैं। ऐसे में स्कूलों में अब विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई है। शिक्षकों को छोड़कर कोई भी शिक्षकेतर कर्मचारी यानी नन टीचिंग स्टॉफ समय से नहीं पहुंच रहे हैं जिससे स्कूल समय पर नहीं खुल रहा है। जबकि शिक्षक स्कूल सुबह 9 बजे के 20 मिनट पहले ही पहुंच रहे हैं। लेकिन वे बाहर से ही अपनी ऑनलाइन हाजरी बनाकर खड़े रहते हैं। क्योंकि 500 मीटर के दायरे तक ऑनलाइन हाजरी बनाने की सुविधा दी गई है। वहीं इन शिक्षकेतर कर्मचारियों के लेट लतीफी के कारण छात्र–छात्राओं को भी स्कूल के बाहर द्वार नहीं ससमय खुलने से खड़े रहना पड़ रहा है।

अब ऐसे में शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ से मांग की है की या तो इस एप के माध्यम से शिक्षकों के हाजरी बनाने की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाय नहीं तो फिर यह ऑनलाइन हाजरी बनाने की अनिवार्यता स्कूल के सभी स्टॉफ के लिए लागू की

जाय। क्योंकि स्कूलों से नन टीचिंग स्टॉफ कई–कई दिनों तक गायब रह रहे हैं और स्कूल आकर पिछले तारीख की हाजरी हेडमास्टर की मिलीभगत से बना ले रहे हैं। इससे स्कूल का माहौल खराब हो गया है और इसका बुरा असर बच्चों के पठन पाठन पर देखने को मिल रहा है।

गौरतलब हो की एप के माध्यम से ऑनलाइन हाजरी बनाने को लेकर शिक्षकों मे खासी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। वहीं कई वर्षों से एक ही स्कूल में घर के आस–पास शिक्षकेतर कर्मचारियों के पदस्थापित होने से कोई भी प्रधानाध्यापक इनके खिलाफ कुछ भी लिखने से मनाही करते हैं। इतना ही नहीं इन स्थानीय शिक्षकेतर कर्मचारियों के द्वारा छात्र–छात्राओं से रजिस्ट्रेशन एवं फॉर्म में भी अधिक पैसे की उगाही की जाती है। एक शिक्षक ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि जबतक इन स्थानीय शिक्षकेतर कर्मचारियों का ट्रांसफर गृह जिले से बाहर अन्य जिलों में नहीं हो जाता है स्कूलों की व्यवस्था नहीं सुधरने वाली है।

खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का होगा आयोजन

गौरव यादव

लखनऊ (संज्ञान दृष्टि)। उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य की पहल व उनके निर्देशों के क्रम में क्षेत्रीय खाद्य अनुसंधान एंव विश्लेषण केन्द्र की लखनऊ में स्थापना के 20 वर्ष पूरे होने पर संस्था द्वारा दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यशाला 16 एवं 17 नवंबर, 2024 को खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता विषय पर उद्यान भवन परिसर में आयोजित होगी। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति व इस क्षेत्र में लोगों को विस्तार से जानकारी देकर जन जागरुकता लाई जाय। इसी उद्देश्य से यह कार्यशाला प्रायोजित की गयी है। इस कार्यशाला में खाद्य प्रसंस्करण व्यवसाय का परिचय, खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता अभ्यास, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण में अवसर, प्रशिक्षण और प्रमाणन खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियाँ (कैनिंग, कूलिंग, निर्जलीकरण), खाद्य मिलावट (लाइव प्रदर्शन), गुणवत्ता नियंत्रण और आश्वासन, और सिद्धांत, खाद्य पैकेजिंग और लेबलिंग, विनियमन और मानक, मूल्यांकन और उत्पाद, विकास बैंक वित्त (सरकारी योजना) आदि विषयों पर विस्तार से जानकारी दी जायेगी। इसमें प्रश्न और उत्तर का सत्र भी होगा। निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग श्री विजय बहादुर द्विवेदी ने बताया कि यह संस्थान मेगा फूड पार्क विकास परियोजनाओं, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अपने विशेषज्ञों की सहायता से, खाद्य निर्माण में लगे और खाद्य पदार्थों के संपर्क में रहने वाले फूड पार्क श्रमिकों को मानव संसाधन, मानव संसाधन विकास, कौशल विकास प्रशिक्षण, खाद्य सुरक्षा कार्यान्वयन प्रशिक्षण, स्वच्छता और सफाई प्रशिक्षण कार्यक्रम जनमानस को उपलब्ध कराते हैं। एफएसएसएआई अधिनियम के अनुसार खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एफएसएमएस) योजना अनिवार्य है, आरएफआरएसी इसके लिए यूपी में नामित नोडल एजेंसी है। आर–एफआरएसी को पीएमएफएमई, केवीआईसी, फोस्टैक, पीएमकेवीवाई और एनआईएएम के साथ प्रशिक्षण भागीदार के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। बताया कि उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा क्षेत्रीय खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र, (आर फ्रैंक) उद्यान भवन, लखनऊ का गठन प्रदेश में रोजगार सृजन, कृषि एवं औद्योगिक सम्पदा के सदुपयोग, कृषको को उनके उपज का अधिकाधिक मूल्य दिलाने तथा खाद्य सुरक्षा गुणवत्ता परीक्षण, खाद्य निर्माण, अनुसंधान, पैक हाउस, कृषि/खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों आदि की स्थापना कराने में तकनीकी मार्गदर्शन, रोजगार परख प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कियान्वयन संचालन एवं विश्व स्तरीय गुणवत्ता के निर्धारित मानको को व्यवहार में लाने के उद्देश्य से वर्ष 2004 में किया गया था। यह संस्थान प्रदेश की उक्त क्षेत्र में कार्य करने एवं मार्गदर्शन करने हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश के क्रम में कार्यरत है। इस संस्थान में अत्याधुनिक विश्वस्तरीय लैब उपकरण स्थापित एवं कियाशील हैं,जिससे उत्पादों की न्यूट्रिशनल वैल्यू, पेस्टीसाइड रेजिड्यू, एमिनों एसिड्स प्रोटीन स्टेराइट्स, एन्टिबायटिक, ट्रासफैट, मेटल्स, माइको बायोला जीकल पैरामीटर, सेल्फ, पानी की सम्पूर्ण जांच, सी०ओ०डी०, बी०ओ०डी०, मिनरल्स, माईको न्यूट्रिएण्ट्स, जैविक उत्पादों का सम्पूर्ण विश्लेषण, पौष्टिक आहार की जांच आदि के कार्य राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार भारत सरकार के (एफ.एस.एस.ए.आई., एपीडा, ऐगमार्क आदि) मानकों के अनुसार की जाती है। आर फ्रैंक के निदेशक एस के चौहान ने बताया कि कार्यशाला और फॉस्टैक के लिए पंजीकरण शुल्क धनराशि रू0–1650 प्रति उद्यमीध्व्यक्ति निर्धारित की गयी है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने पर प्रतिभागियों को आरएफआरएसी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दोहरा प्रमाण पत्र और भारत सरकार द्वारा फॉस्टैक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। इस कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले उद्यमियों, छात्रों, महिलाओं आदि को निम्न लाभ प्राप्त हो सकेगें खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाना और प्रतिभागियों को उद्यम शीलता कौशल प्रदान करना। प्रतिभागी अपने दैनिक जीवन, शोध कार्य या व्यावसायिक उपक्रमों में व्यावहारिक तरीकों से सीखी गई बातों को लागू करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होंगे।

शरद पूर्णिमा पर स्वच्छ गंगा का संदेश, घाट किनारे चलाया गया सफाई अभियान

संज्ञान दृष्टि टीम

वाराणसी (संज्ञान दृष्टि)। वाराणसी में नमामि गंगे की टीम द्वारा शरद पूर्णिमा पर स्वच्छता अभियान चलाकर संदेश देने का काम किया गया। इस दौरान मोक्षदायिनी की आरती भी उतारी गई। शरद पूर्णिमा पर हर–हर गंगे की गूंज के बीच नमामि गंगे ने दशाश्वमेध घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया । जन–जन को स्वच्छता से जुड़ने की अपील करके नमामि गंगे ने मां गंगा की आरती उतारी। पॉलिथीन कचरा तथा गंगा में श्रद्धालुओं द्वारा विसर्जित की गई पूजा सामग्री के अवशेषों को गंगा के जल से बाहर निकाला गया। गंगा को स्वच्छ रखने के लिए लाउडस्पीकर से श्रद्धालुओं को जागरूक किया गया।

नमामि गंगे की टीम को देख वहां पहुंचे श्रद्धालुओं ने भी टीम का साथ दिया। उन्होंने मां गंगा की आरती उतारकर स्वच्छता का संकल्प लिया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम ब्रांड एंबेसडर राजेश शुक्ला ने बताया कि हमारे सभी धार्मिक ग्रंथो एवं शास्त्रों ने पर्यावरण के संरक्षण का संदेश दिया है।

वेदों और पुराणों में वर्णन मिलता है मनुष्य को अपने किसी भी कृत्य से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आयोजन में विशेष रूप से उपस्थित राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नई दिल्ली के प्रतिनिधि अथर्वराज पाण्डेय ने गंगा सफाई के लिए एकजुट होकर जन भागीदारी सुनिश्चित करने का आवाह्न किया।

बहराइच में शुरू हुई इंटरनेट सेवा, महाराजगंज में 10 प्रतिशत दुकानें खुलीं, पुलिस बल मौजूद

संज्ञान दृष्टि टीम

बहराइच (संज्ञान दृष्टि)। बहराइच जिले के महसी तहसील क्षेत्र के महाराजगंज कस्बे में बीते रविवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो पक्षों में हुए विवाद के बाद स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई थी। इस घटना में एक युवक की गोली मारकर हत्या भी की गई है। वहीं, तीन युवक घायल हुए हैं।बीते चार दिनों से यहां पर इस घटना के बाद आघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल था और इंटरनेट की सेवाएं पूरे जिले में बंद कर दी गई थी। हालांकि अब स्थिति सामान्य हो रही है। बृहस्पतिवार को प्रभावित इलाका महाराजगंज में दुकानें खुली हैं और ज्यादातर दुकानें बंद है। यहां के बैंक भी खोले गए हैं। इससे धीरे–धीरे क्षेत्र में माहौल शांति मय हो रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ दिनों में ही माहौल पूरी तरह सामान्य हो जाएगा। यहां पर सुरक्षा के लिए अभी भी पुलिस फोर्स का कड़ा पहरा है। अधिकारी लगातार कैंप कर रहे हैं। डीएम, एसपी द्वारा लगातार भ्रमण किया जा रहा है लेकिन पुलिस द्वारा लोगों को छूट दी गई है और बेवजह किसी को परेशान नहीं किया जा रहा है। जिले में इंटरनेट सेवा भी बुधवार देर रात को खोल दी गई है जिससे लोगों को काफी राहत मिली है।

सीडीओ ने किया टीएचआर प्लांट का औचक निरीक्षण, स्टॉक मिलान में पकड़ी अनियमितता

स्पर्श सिन्हा

'लखीमपुर खीरी (संज्ञान दृष्टि)। गुरुवार को सीडीओ अभिषेक कुमार ने तहसील मितौली के ग्राम रेवाना में संचालित आदर्श प्रेरणा लघु उद्योग ''टीएचआर प्लांट'' का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान स्टॉक सत्यापन में अनियमितता सामने आई, जिसके चलते बीएमएम आशीष कुमार दीक्षित का मानदेय बाधित कर दिया गया और विभागीय जांच के निर्देश दिए गए। स्टॉक रजिस्टर को भी कब्जे में लिया गया। इसके अलावा, डीसी एनआरएलएम को प्लांट का ऑडिट कराने के भी निर्देश दिए गए।

निरीक्षण के दौरान सीडीओ ने स्टॉक रजिस्टर का अवलोकन किया और गिनती कराकर स्टॉक का मिलान कराया। स्टॉक में दाल की बोरियां कम पाई गईं, जबकि तेल के पीपे अधिक मात्रा में मिले। बीएमएम द्वारा पूछे जाने पर संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पाया, जिससे सीडीओ ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, ''स्टॉक मिलान से स्पष्ट है कि अधिक या कम सामग्री मिलना अनियमितता का संकेत है।''

इस अवसर पर सीडीओ ने प्लांट संचालन और उत्पादन के संबंध में संचालक दीदीओ से बातचीत की। उन्होंने टीएचआर निर्माण प्रक्रिया का अवलोकन किया और राशन की गुणवत्ता की जांच की। सीडीओ ने पोषण बनाने वाली मशीन और उसकी प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली, साथ ही पोषण के मानकों को पूरा रखने का निर्देश दिया। उन्होंने साफ–सफाई और मानकों का ध्यान रखने की भी सलाह दी। वजन मशीन से उत्पाद का वजन करवाने के बाद, तैयार पुष्टाहार की गुणवत्ता की भी जांच की गई। सीडीओ ने निर्देश दिए कि प्लांट पर निर्मित होने वाले पुष्टाहार की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। निरीक्षण में प्लांट संचालित और क्रियाशील पाया गया।

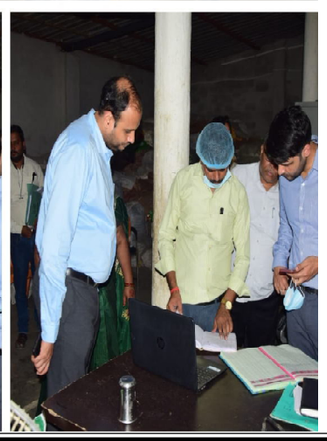

जेसीबी से झोपड़ी और कच्चे घर गिराए गए अफरातफरी

घनश्याम गुप्ता

सतावं रायबरेली (संज्ञान दृष्टि)। गुरबक्श गंज क्षेत्र के चंदवल गांव में बुधवार को जेसीबी झोपड़ियां और कच्चे घरों पर चली तो अपरा तफरी मच गई! ग्रामीणों ने डायल 112 पुलिस को सूचना दी इस पर पुलिस पहुंचने की भनक लगते ही कब्जा करने आए लोग आनंन फानन में जेसीबी छोड़कर भाग गए !पुलिस ने जेसीबी को कब्जे में ले लिया है मामले में 50 लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई जिसमें चंदवल गांव निवासी श्री राम, गंगा चरन, गोकरन, राजकरन आदि ने थाने पर दी गई तहरीर में बताया की गांव पूरे रामदीन मजरे मलिक मऊ चौबारा निवासी एक व्यक्ति अपने साथ करीब 50 लोगों को लेकर गांव पहुंचा उसके साथ जेसीबी भी थी बताया कि बिना किसी को कुछ बताया जेसीबी से झोपड़ी और कच्चे घर गिराए गए! थाना प्रभारी बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर पड़ताल की जा रही है!

सागाही मे रामलीला कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ

रंजीत कुमार

गुरुआ (संज्ञान दृष्टि)। गुरूआ के सागाही गॉव मे मंगलवार को यंग सोसाइटी क्लब सागाही को रामलीला कार्यक्रम का आयोजन हुआ आयोजित रामलीला कार्यक्रम उद्घाटन का राजन पंचायत उपमुखिया अमन पाल ने फीता काटकर किया।

रामलीला का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा की रामलीला, रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन है. यह भगवान राम की कहानी है और इसमें उनके वनवास से लौटने का जश्न मनाया जाता है. रामलीला में देवताओं, ऋषियों, और विश्वासियों के बीच संवादों की एक श्रृंखला होती है। मौके पर क्लब के अध्यक्ष जितेंद्र यादव, क्लब के कोषाध्यक्ष अरविंद यादव, अजय पासवान सतीश गुप्ता विकास कुमार एवं समेत सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे।

एक नज़र

दिल्ली– कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने एक्स पर लिखा, बिहार में जहरीली शराब से अब तक 36 मौतें हुई–खरगे, लोगों की मृत्यु बेहद पीड़ादायक और दुःखद है खरगे, पीड़ितों के शोकाकुल परिजनों को गहरी संवेदनाएं–खरगे, 'सरकार से अनुरोध दोषियों को कड़ी, सजा दिलवाई जाए', 'इससे पहले अवैध शराब से कई लोगों ने जान गंवाई है', 'बिहार सरकार अवैध शराब का कारोबार रोकने में विफल'।

मेरठ– छेड़छाड़,मारपीट के पीड़ित परिवार पर फैसले का दबाव, फैसला नहीं करने पर डराया धमकाया जा रहा, दबंगों ने किशोरी से छेड़छाड़ कर परिवार पर हमला बोला, किशोरी के माता–पिता की पिटाई कर हाथ तोड़ा था, मुकदमा दर्ज, थाना पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं की, एसएसपी से दूसरे थाने में जांच ट्रांसफर करने की गुहार, थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र के खड़ौली गांव का मामला।

उन्नाव– उन्नाव पुलिस और एसओजी टीम को मिली सफलता, जाली नोट छापने, तस्करी करने वाला गिरोह चढ़ा हत्थे, दो लाख 95 हजार 800 रुपये के जाली नोट बरामद, चेकिंग के दौरान कार से 500 रुपये 394 जाली नोट बरामद, 100 रुपये के 988 जाली नोट, एक एप्सन प्रिंटर बरामद, मॉडम, मॉनिटर, सीपीयू, पेपर कटर, लैपटॉप अन्य चीजें बरामद, एसओजी, पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर की कार्रवाई, औरास के कटरा तरौना पुल के पास से किया गिरफ्तार।

हापुड़– हापुड़ में भारत समाचार की खबर का बड़ा असर, खबर का डीएम, गढ़ैक्ड ने संज्ञान लिया, भ्रष्ट लेखपाल का रिश्वत लेने के मामले में कार्रवाई, भ्रष्ट लेखपाल साबिर को सस्पेंड किया, लेखपाल ने सहयोगी दीपक के साथ ली थी रिश्वत, रिश्वत कांड में पहले भी सस्पेंड हो चुका लेखपाल साबिर, फर्द में नाम चढ़ाने के नाम पर लेखपाल ने ली थी रिश्वत, गढ़ तहसील में तैनात है भ्रष्ट लेखपाल साबिर।

कन्नौज– सपा एमएलसी लाल बिहारी यादव का बड़ा बयान, बहराइच में हुआ दंगा सुनियोजित था–लाल बिहारी, भाजपा हिन्दू मुस्लिम दंगों को बनाती है मुद्दा–लाल बिहारी, पार्लियामेंट चुनाव से बीजेपी बहुत डरी है लाल बिहारी, इसीलिए मिल्कीपुर सीट से नहीं की घोषणा–लाल बिहारी, बहराइच दंगा पुलिसिया चूक का नतीजा है–लाल बिहारी, सपा का डेलीगेशन दोनों पक्षों के घर जाएंगे–लाल बिहारी।

यदि आप संज्ञान दृष्टि पर कोई विज्ञापन देना चाहते है या किसी अन्य प्रकार के व्यावसायिक अनुबंध के इच्छुक है तो हमे
sangyandristinewspaper@gmail.com
पर ईमेल कर सकते हैं।
व्हाटसएप नम्बर
+91–7080049049

व्हाट्सएप पर सम्पर्क के लिए
70800–49049
95824–49049
Website :
www.sangyannews.com
sangyandrsitinewspaper@gmail.com

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक प्रांजल श्रीवास्तव द्वारा मंजुला आफसेट, काशीनगर, लखीमपुर–खीरी से मुद्रित तथा 132/2 काशीनगर चोपड़ा इंडस्ट्री लखीमपुर–खीरी, उ0प्र0 से प्रकाशित

सम्पादक– प्रांजल श्रीवास्तव

(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी)

रेवाना गांव पहुंचकर सीडीओ ने किया निरीक्षण, परखी व्यवस्थाएं

पीएम आवास के लाभार्थी नीरज के घर पहुंचे सीडीओ, किया संवाद

सीडीओ की पहल पर, रेवानावासियों को मिलेगा अपने घर का हाउस नंबर, वार्डवार आवंटित होंगे मकान नंबर

अमित अवस्थी

लखीमपुर खीरी (संज्ञान दृष्टि)। गुरुवार को सीडीओ अभिषेक कुमार ने ग्राम पंचायत रेवाना पहुंचकर पंचायत भवन, क्लस्टर आवास, अन्नपूर्णा भवन सामुदायिक शौचालय का औचक निरीक्षण किया।

सीडीओ ने ग्राम पंचायत रेवाना में क्लस्टर आवासों का अवलोकन करते हुए लाभार्थियों से संवाद भी किया। उन्होंने पंचायत भवन पहुंचकर परिवार रजिस्टर, जन्म मृत्यु रजिस्टर, ग्रामसभा कार्यवाही रजिस्टर, मनरेगा रजिस्टर, सहित विभिन्न पंजिकाओं का अवलोकन किया। पंचायत भवन में सीसीटीवी कंट्रोल रूम को भी देखा। निर्देश दिए की आवास रजिस्टर में लाभार्थी का मोबाइल नंबर भी अंकित किया जाए। नवाचार करते हुए ग्राम पंचायत में वार्डवार मकान नंबर भी आवंटित किए जाएं। मनरेगा के तहत कराए गए कार्यों की अनुरक्षण पंजिका का भी अवलोकन किया। आवास पात्रता रजिस्टर को देखते हुए ग्राम सचिव को निर्देशित किया कि कोई भी पात्र व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास पानी से वंचित न रहने पाए।

इसके बाद गांव में नव निर्मित अन्नपूर्णा भवन का भी अवलोकन किया। बीडीओ को निर्देश दिए कि संपर्क मार्ग से अन्नपूर्णा भवन के पहुंच मार्ग को यथाशीघ्र बनवाया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी नीरज कुमार पुत्र ज्वाला प्रसाद के घर पहुंचे, जहां घर पर मौजूद उनकी बहन शीतल देवी से संवाद किया। जाना कि आवास में किसी ने कोई सुविधा शुल्क तो नहीं लिया है जवाब आया नहीं साहब! जिला पंचायत द्वारा गांव में लगी स्ट्रीट लाइट खराब मिली, इसे तत्काल ठीक कराने के निर्देश दिए। गांव की मधुबाला ने सीडीओ से शौचालय बनवाने की मांग की। सचिन ने बताया कि इनका ऑनलाइन आवेदन और सत्यापन हो चुका है शीघ्र ही अनुमन्य धनराशि अंतरित कर दी जाएगी।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोजित विशेष पखवाड़े में 1215 वृद्धजनों को मिली स्वास्थ्य सेवाएं

अमित अवस्थी

लखीमपुर खीरी (संज्ञान दृष्टि)। एनसीडी एनपीएचसीई कार्यक्रम के अंतर्गत 1 अक्टूबर से जिला चिकित्सालय मोतीपुर ओयल में मनाया जा रहे हैं पखवाड़े के बाद सलेमपुर कोन स्थित वृद्धा आश्रम में एक हेल्थ कैंप लगाकर कार्यक्रम का समापन किया गया। इस दौरान फल वितरण के साथ ही जिला चिकित्सालय के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा साठ वृद्धजनों को स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान की गई। वहीं विशेष पखवाड़े के अंतर्गत जिला चिकित्सालय में चलाई जा रही ओपीडी में 1215 वृद्धजनों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्राप्त किया है। सीएमएस डॉ आरके कोली ने बताया कि एनसीडी के अंतर्गत एनपीएचसीई कार्यक्रम संचालित है। इसी कार्यक्रम के तहत 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए एक विशेष पखवाड़ा मनाया गया, जिसमें जिरियाट्रिक फिजिशियन और एनपीएचसीई कार्यक्रम के जिला चिकित्सालय के नोडल डॉ शिखर बाजपेई द्वारा 536 वृद्धजनों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई। इसी तरह मानोचिकत्सक द्वारा 132 वृद्धजनों को, ऑर्थोपेडिक सर्जन द्वारा 227 मरीजों को और नाक कान गला रोग विशेषज्ञ द्वारा 151 मरीज के साथ नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा 169 वृद्धजनों को इस पखवाड़े के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा दी गई। इसके बाद कार्यक्रम का समापन 16 अक्टूबर को वृद्धा आश्रम सलेमपुर कोन में स्वास्थ्य शिविर लगाकर दिया गया, यहां पर जिरियाट्रिक फिजिशियन डॉ शिखर बाजपेई, मनोचिकित्सक डॉ अखिलेश शुक्ला, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ विनय, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉ मनोज शर्मा सहित हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ श्रीराम द्वारा कैंप लगाकर 60 वृद्धजनों को देखा गया और उन्हें दवाई भी वितरित की गई। इस दौरान स्टाफ नर्स विवेक मित्तल व नेहा परवीन ने सहयोग किया। वहीं सीएमओ ऑफिस से एनसीडी टीम में एपिडेमियोलॉजी डॉ राकेश गुप्ता व विजय वर्मा द्वारा तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत शपथ ग्रहण कराकर लोगों को तंबाकू उत्पादों के नुकसान से जागरूक किया गया साथ ही वृद्धजनों के सम्मान में फल वितरण भी किया गया।

ऐरा चीनी मिल के तीसरी बार डायरेक्टर चुने गए राम नरेश मिश्रा

राजू सिंह अध्यक्ष और विजय प्रताप सिंह उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित

शत्रोहन लाल राजपूत, राजकिशोर चौधरी के सात समर्थक रमेश सिंह , ज्ञानेंद्र वर्मा, अभय प्रताप सिंह, संतोष मिश्रा, राजकुबेर सिंह, खिलाड़ी सिंह, कमलेश भार्गव, गुड्डू सिंह, लाल बहादुर सिंह मौजूद रहे।

अमित अवस्थी

'ऐरा खमरिया'लखीमपुर–खीरी (संज्ञान दृष्टि)। धौरहरा तहसील क्षेत्र की गन्ना विकास समिति ऐरा में गुरुवार को पुलिस सुरक्षा के बीच तीसरी बार गांव सेमरी निवासी राम नरेश मिश्रा को डायरेक्टर के पद पर नामित किया गया। श्री मिश्रा को डायरेक्टर चुने जाने पर उनके समर्थकों ने उन्हें मिठाई खिलाकर व माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत कर शुभकामनाएं दिया स इस अवसर पर विधायक विनोद शंकर अवस्थी ने कहा कि राम नरेश मिश्रा भाजपा संगठन के बहुत ही निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ता हैं स जोकि धौरहरा के गांव सेमरी से आकर जिले की राजनीति करना अपने आप में प्रमाण हैं स और अपनी कुशल कार्यशैली व मेहनतकश स्वभाव के चलते राम नरेश मिश्रा तीसरी बार डायरेक्टर चुने गए हैं।

विधायक श्री अवस्थी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ऐसे सक्षम एवं निष्ठावान कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का काम कर रही है स इसी का नतीजा है कि आज राम नरेश मिश्रा को उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना विकास समिति में लगातार तीसरी बार डायरेक्टर के पद पर सरकार द्वारा नामित किया गया है।

वहीं अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई जिसमें डायरेक्टर पद पर चुने गए मूड़ी निवासी राजू सिंह ने अध्यक्ष पद के लिए और हरदासपुर निवासी विजय प्रताप सिंह ने उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। निर्धारित समयावधि तक कोई अन्य नामांकन पत्र नहीं खरीदा गया। जिसके चलते निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार ने ऐरा गन्ना विकास समिति के अध्यक्ष पद पर राजू सिंह व उपाध्यक्ष पद पर विजय प्रताप सिंह को निर्विरोध निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए शुभकामनाएं दी।

इस मौके पर उपस्थित नवनिर्वाचित डायरेक्टर उत्तरा सिंह, भानु प्रताप सिंह, कमल किशोर सिंह, होशियार बक्श सिंह, सरयू प्रकाश पांडे, संतोष कुमारी, अमरीश भार्गव,

रौशनगंज थाना अध्यक्ष के कार्यशैली को थाना क्षेत्र के ग्रामीण खूब कर रहे सराहना

रंजीत कुमार

गया (संज्ञान दृष्टि)। गया जिला रौशनगंज थाना के थानेदार अंगद पासवान की इनदिनों क्षेत्र में लोगों के लिए चर्चा का विषय बने हुए है। लोग बताते हैं की रौशनगंज थाने में कितने थानेदार आए और गए लेकिन चाय पिलाकर समस्या पूछने वाले थानेदार पहली बार आए हैं। गरीब शोषित या दवे कुचले लोगों के लिए इन दिनों वरदान साबित हो रहे हैं। पहले लोग थाना जाने के नाम पर थर–थर कापते थे और पीड़ित गरीब लोग दलालों दुबारा अपनी समस्या को रखते थे। वही इस विषय में अंगद पासवान का कहना है कि थाने से संबंधित कोई भी मामला है तो निडर होकर अपनी समस्या को लेकर थाने पहुंचे और हमसे मुलाकात करें उनकी समस्या को हर संभव निदान करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि दलाल के चक्कर में न रहे। आपकी काम बनने के वजह बिगड़ सकती है।

इतना ही नहीं अपराधी तत्व के लोग उनके नाम से थर कापते हैं। ग्रामीणों ने बातचीत के दौरान बताया कि अंगद पासवान जैसे विचारधारा के थानेदार हर थाने में होना चाहिए. ताकि लोगों की परेशानियां सुना जा सके। उन्होंने आगे बताया कि अंगद पासवान पीड़ित और लाचार लोगों को थाने में बैठाकर इज्जत और सम्मान के साथ चाय पिलाकर दोनों पक्षों की समस्या सुनते हैं और उचित फैसला करते हैं जिससे क्षेत्र में उनकी वाह वाही हो रही है। बताते चलें कि रोशनगंज थाना क्षेत्र के विभिन्न ऐसे गांव हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र से गुजरता है। लेकिन इसके बावजूद भी बिना डर भय के जान जोखिम में डालकर मर्डर केस के अभियुक्त हो या वारंटी को पकड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि रात हो या दिन इस थानेदार के लिए दोनों बराबर है जब भी किसी तरह का घटना हो या दुर्घटना वह तुरंत पहुंच जाते हैं। इतना ही नहीं उनके कार्रवाई से शराब माफिया अपना रास्ता बदल दिए हैं।

समाजसेवी हरिओम तिवारी 'राघवचरणानुरागी' ने जरूरतमंद को सौंपी दवाईयां

संतोष मौर्य

अयोध्या (संज्ञान दृष्टि)। किसी भी प्रकार के जरूरतमंद को हर प्रकार की संभव मदद फिर वो चाहे सामाजिक हो या आर्थिक करना ही मेरा जीवन का प्रथम लक्ष्य है।

मेरे जीवन का ध्येय है कि सहायता के लिये आया कोई भी व्यक्ति मेरे दरवाजे से खघली हाँथ न लौटे। बताते चलें कि अमानीगंज के जखघ्वा गाँव निवासी रामकुमार अवस्थी जो कि हृदय आदि संबंधी बीमारियों से परेशान थे, तथा आर्थिक समस्याओं के कारण वो दवाई लेने में असमर्थ थे। उक्त परेशानी साझा करने जब वो हरिओम तिवारी के आवास पर पहुँचे, तो उन्होंने तुरंत अपने सहयोगी से दवा मँगवाकर उन्हें लाभ प्रदान किया तथा जरूरत पड़ने पर अन्य मदद का भी आश्वासन दिया।

ज्ञातव्य हो कि हरिओम तिवारी पूर्व में भी रामकुमार अवस्थी की पत्नी के बीमारी में भी उनकी आर्थिक सहायता कर चुके हैं। तथा प्रति वर्ष दर्जनों गरीब कन्याओं के विवाह, बेरोजगारों को अपनी फैक्ट्री में रोजगार देना, छात्र, छात्राओं की पढ़ाई में मदद, आदि सामाजिक करते रहते हैं।

हरिओम तिवारी इस नेक इस नेक कार्य के पीछे मुख्य प्रेरणास्रोत ईश्वर की मर्जी को बताते हैं ।

मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला शब्द पाळला : माजी खासदार हेमंत पाटील यांना दुबार लॉटरी

पाटलांना 'कॅबिनेट'नंतर आता आमदारकी

सय्यद मुदस्सीर

यवतमाळ (संज्ञान दृष्टी)। यवतमाळ मुख्यमंत्री शिंदे यांनी राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्ण यांच्याकडे शिफारस केलेल्या नावांमध्ये हिंगोलीचे माजी खासदार हेमंत पाटील यांचे नाव असल्याची खात्रीलायक माहिती आहे. काही दिवसांपूर्वीच त्यांना कॅबिनेट मंत्री पदाचा दर्जा दिला होता. त्यात आता विधान परिषदेसाठीही पाटील यांचे नाव आहे. त्यांच्यासाठी दुबार लॉटरी आहे. विधान परिषदेची आचारसंहिता कोणत्याही क्षणी लागू शकते. त्यामुळे रखडलेले निर्णय घेण्याचा सपाटा सरकारने लावला आहे. विधान परिषदेच्या माध्यमातून राजकीय पूनर्वसन मा.बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन केंद्राचे अध्यक्ष तथा शिवसेना उपनेते हेमंत पाटील यांना राज्य शासनाने १६ सप्टेंबर रोजी कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा दिला होता. केंद्र व राज्य सरकारचा संयुक्त प्रकल्प असलेल्या हळद संशोधन केंद्राचे अध्यक्ष म्हणून त्यांना हा कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि महायुती सरकारने घेतला. या निर्णयाला महिना होतो न होता, हेमंत पाटील यांच्या नावाची राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी शिफारस केली आहे. कॅबिनेट मंत्री दर्जा, आता आमदारकी देवून पाटील यांचे राजकीय पुनर्वसन करण्यात येत आहे. मागील अडीच वर्षांपासून रखडलेल्या राज्यपाल नियुक्त विधान परिषदेच्या १२ जागा भरण्यासाठी हालचालींना वेग आला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सात नावांची शिफारस केली आहे, अशी माहिती आहे. लोकसभा निवडणुकीत हेमंत पाटील यांचे तिकीट कापून राजश्री हेमंत पाटील यांना यवतमाळमधून उमेदवारी दिली होती. परंतु, त्यांचा पराभव झाला. मात्र, मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पाटील यांना दिलेला शब्द पाळत त्यांच्या नावाची राज्यपाल नियुक्त शिफारस केली आहे. सदस्य म्हणून निवड करण्यासाठी यापूर्वी माजी खासदार भावना गवळी यांनाही विधान परिषद देवून त्यांचे राजकीय पुनर्वसन केले होते. आता हेमंत पाटील यांनादेखील विधान परिषद देवून त्यांचे राजकीय पुनर्वसन करण्यात येत आहे.

सोयाबीनचे भाव पडल्याने शेतकरी नाराज विधानसभा निवडणुकीत दिसणार पडसाद, लागवडीचा खर्चही निघत नसल्याची चर्चा

सय्यद मुदस्सीर

यवतमाळ (संज्ञान दृष्टी)। यवतमाळ शेतात किती पिकले यापेक्षा शेतमालाला भाव किती हा प्रश्न आज महत्त्वाचा आहे. यंदा चांगला पाऊस झाला, पीकपाणी चांगले आहे. परंतु, ऐन सोयाबीन काढणीला आले आणि हमीभाव गडगडले. त्यामुळे लागवडीचाही खर्च निघणे कठीण असल्याने शेतकरी नाराज आहेत. याचा परिणाम या विधानसभा निवडणुकीवर होणार असल्याचे चित्र दिसत आहे.

खरीप हंगामात सर्वाधिक उत्पादन सोयाबीनचे घेतले जाते. यावर्षी मोठ्याप्रमाणात सोयाबीनची लागवड करण्यात आली. यंदा लागवड खर्चही वाढला. सोयाबीनला योग्य भाव मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर उमटत आहे. तर नवीन सोयाबीन विकावे की की साठवून घरीच ठेवावे? असा प्रश्न शेतकरी बांधवांना पडला आहे. सध्यातरी शेतकरी भाववाढीच्या प्रतीक्षेत आहेत. महागाव व परिसरात सोयाबीन काढण्याची लगबग सुरू झाली आहे. त्यामुळेबाजार समितीत सोयाबीनची आवक वाढत आहे. चांगल्या भावासाठी शेतकरी सोयाबीन उगमफाटा येथे नेत आहेत. मात्र यावर्षी सोयाबीनाला चांगला भाव राहील, अशी अपेक्षा होती. परंतु ती अपेक्षाच फोल ठरली आहे. सोयाबीनचे भाव गडगडले.

आज सोयाबीन चार हजार ते ४.हजार ३०० रुपये प्रतिक्विंटल होते. सोयाबीन बियाण्याचे, खताचे व कीटकनाशकाचे दर मात्र मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. दुसरीकडे सोयाबीनचा लागवड खर्च अधिक आहे. मात्र, त्या तुलनेत भाव खूपच कमी मिळत आहे. कधी अतिवृष्टी, कधी किडीचा प्रादुर्भाव, कधी परतीच्या पावसाचा तडाखा यामुळे यामुळे उत्पादनात घट होत आहे. त्यात दर घसरल्याने शेतकऱ्यांचे मनोबल खच्ची होत आहे.

सोयाबीनच्या भावात घसरण

मागील दहा दिवसांपासून तालुक्यात सोयाबीन काढणी सुरू आहे. सोयाबीनला हमीभावही मिळत नाही. त्यामुळे शेतकरी चिंताग्रस्त झाले आहेत. गेल्या वर्षीही सोयाबीनला चांगले दर मिळाले नाही. यावर्षी तरी चांगला भाव मिळेल, अशी अपेक्षा होती. यंदा सोयाबीनला कमी भाव मिळत आहे. त्यामुळे सोयाबीनचे पीक घ्यावे की नाही? असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे.

३७०० ते चार हजार रुपये भाव

'बाजारपेठेत सोयाबीनची चांगलीच घसरण पाहायला मिळत आहे. बाजारपेठेत सोयाबीन ३७०० ते चार हजार रुपये प्रतिक्विंटल दराने खरेदी केले जात आहे. सद्यःस्थितीत सोयाबीन काढणीला खर्च अधिक येत आहे. कापणीसाठी साडेचार हजार रुपये दहा दिवसांपासून सोयाबीन काढणी सुरू आहे. सद्यःस्थितीत शेतकऱ्यांना सोयाबीन कापणीसाठी एका बंगला साडेचार हजार रुपये द्यावे लागत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे पुढील हंगामाचे नियोजन ढेपाळले आहे. मजुरी जास्त लागत असल्योने अनेक शेतकरी घरीच सोयाबीनची कापणी करीत आहेत.